सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक का आह्वान

- नयी आर्थिक नीति का प्रतिरोध करो !
- युद्ध की साम्राजी मुहिम के खिलाफ संघर्ष तेज करो!
- सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत करो !
- फूट परस्त ताकतों का मुकाबला करो !

दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर तक हुई अपनी बैठक में सीटू वर्किंग कमेटी ने युद्ध की साम्राजी साजिशों के खिलाफ तथा शांति के लिए संघर्ष करने; फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला करने तथा देश की एकता व अखण्डता की रक्षा करने के लिये मजदूरों तथा जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सभी तबकों को लामबंद करने; देश की सरकार की घोर प्रतिगामी नयी आर्थिक नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करने और देशी इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ से सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत करने का जोरदार आह्वान किया है.

साठ वर्किंग कमेटी सदस्यों तथा कुछ विशेष आमंत्रितों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. सीटू महासचिव समर मुखर्जी तथा चार अन्य वर्किंग कमेटी सदस्य बैठक के समय बिदेश में थे. सीटू कोषाध्यक्ष ई बालानंदन बर्लिन में हुई वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस की ग्यारहवीं कांग्रेस में हिस्सा लेने के बाद लौटे थे और दूसरे दिन की बैठक में ही शामिल हो सके. सीटू सचिव कमल सरकार, अपने इलाज के लिए पीकिंग गये हुए हैं. वर्किंग कमेटी के दूसरे कई सदस्य भी बीमारी या दूसरे अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके.

बैठक का उद्घाटन करते हुए बी टी रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्थिति की चुनौतियों को रेखांकित किया और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन तथा आंदोलन की सुनियोजित प्रगति की जरूरत पर जोर दिया (बी टी आर के अध्यक्षीय भाषण हम पिछले अंक में प्रकाशित कर चुके हैं).

पी के गांगुली के संयोजकत्व में एक प्रस्ताव उप-समिति जिसमें पी सांझगिरी, पी बी चेरियन, सुनील बसुराय तथा ए के पद्मनावन थे तथा पी सत्यनारायण के संयोजकत्व में एक क्रेडेंशियल उप-समिति जिसमें चित्व्रत मजुमदार, सी जी पाउलस व रंजित बसु थे, के चुनाव के साथ बैठक की कार्रवाई शुरू हुई.

कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री तथा वर्किंग कमेटी सदस्य शांति घटक तथा सीटू सचिव पी के गांगुली ने श्रम सम्बन्धी स्थाई समिति (स्टैंडिंग लेबर कमेटी) की बैठक की रिपोर्ट पेश की. यह बैठक 22 तथा 23 सितम्बर को दिल्ली में हुई थी. सरकार की ओर से औद्योगिक विवाद कानून तथा ट्रेड यूनियन कानून में प्रतिगामी संशोधन करने और ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर तथा हड़ताल के मजदूरों के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है. पी के गांगुली ने प्रस्ताव किया कि सरकार की इन चालों का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकार किया जाय. एन प्रसाद राव तथा नीरेन घोष ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और एक प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के सुझाव का समर्थन किया. इस प्रश्न पर बहस का समापन करते हुए, बी टी रणदिवे ने प्रस्ताव उप-समिति को इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया. बाद में पी के गांगुली ने प्रस्ताव रखा तथा ए के पद्मनाभन ने उसका समर्थन किया. प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए एन प्रसाद राव, नृसिंह चक्रवर्ती, शांति घटक तथा जी एस बालाजी दास ने कुछ सुझाव रखे, जिनकी रौशनी में संशोधन किए जाने के बाद, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

इसके बाद एम के पंधे ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की कन्वेंशन की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की. यह कन्वेंशन 21 तथा 22 अक्तूबर को नयी दिल्ली के मवालंकार हाल में होने जा रही है. एम के पंधे ने सरकार की नयी अर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व घटाया जा रहा है और उसके मुकाबले में निजी इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि इस चाल का, इंटक समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने ही नहीं बल्कि, अनेक जाने-माने लोगों, अर्थशास्त्रियों और सार्वजनिक क्षेत्र अफसरान एसोसिएशनों की कन्फेडरेशन ने भी जोरदार बिरोध किया है. उन्होंने आग्रह किया कि प्रस्तावित कन्वेन्शन को सफल बनाने के लिए विभिन्न यूनियनें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लामबंद करें

महासचिव की रिपोर्ट

समर मुखर्जी के अनुपस्थित होने के कारण रिपोर्ट औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की जा सकी. रिपोर्ट पहले ही वितरित की जा चुकी थी, इसलिए अध्यक्ष ने रिपोर्ट पर सीधे बहस शुरू करने का निर्देश दिया.

महासचिव की रिपोर्ट में, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटना बिकास की पृष्ठभूमि में, पिछली जनरल काउंसिल बैठक की अवधि में राज्य इकाइयों तथा यूनियनों की गतिविधियों की समीक्षा की गयी थी. शांति के लिए संघर्ष, मई दिवस शताब्दी के पालन, फूटपरस्त ताकतों के बढ़ते खतरे के खिलाफ संघर्ष, सरकार की नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत के लिए संघर्ष, बढ़ती बेकारी तथा तालाबंदी के खिलाफ संघर्ष और कामगार महिलाओं तथा असंगठित मजदूरों को संगठित करने आदि से सम्बन्धित कार्रवाइयों पर महासचिव की रिपोर्ट में खासतौर पर गौर किया गया. अध्यक्षीय भाषण में रेखांकित किये गये राजनीतिक कामों की रौशनी में महा-

सचिव की रिपोर्ट में, मई दिवस की क्रांतिकारी परम्पराओं पर कायम रहते हुए, मई दिवस शताब्दी के पालन का आत्मालोचनात्मक विश्लेषण किया गया. बेरोजगारों की समस्याओं तथा कामगार महिलाओं की समस्याओं पर एक दिवस के पालन तथा कन्वेन्शनों के आयोजन; 11 मई की सांप्रदायिकताविरोधी राष्ट्रीय कन्वेन्शन तथा 9 अगस्त को राष्ट्रीय एकता दिवस के पालन; 21 मई को सार्वजनिक क्षेत्र बचाओ दिवस, 16 जून को रंगभेदविरोधी दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस तथा 1 सितम्बर को शांति के लिये ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के पालन पर विशेष रूप से गौर किया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि रंगभेदविरोधी दिवस के पालन तथा कामगार महिलाओं के सम्बन्ध में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन को छोड़कर उपर्युक्त सभी फैसलों को कमोबेश सफलता के साथ लागू किया गया. रिपोर्ट में इस तथ्य पर गौर किया गया कि असंगठित मजदूरों को संगठित करने के कार्यक्रमों की दिशा में भी एक शुरूआत हुई है. रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया कि जहां कहीं भी राज्य कमेटियों ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहल की है, मजदूरों ने तथा आम जनता ने बढ़-चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इसी क्रम में महासचिव की रिपोर्ट में, ऐसे कार्यक्रमों के लिए पहल न करने तथा केंद्र को समुचित रिपोर्ट न भेजने के लिए, कुछ राज्य कमेटियों की आलोचना भी की गयी.

आंदोलनों तथा कार्रवाइयों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में संघर्षों की, सीटू की एकताकारी भूमिका की तथा इस सिलसिले में सफलता-असफलता की समीक्षा करने पर जोर दिया गया. किसानों तथा खेतमजदूरों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए कुछ राज्य कमेटियों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सराहना की गयी और राज्य कमेटियों का आह्वान किया गया कि अपने रोजमर्रा के संघर्षों में खेतमजदूरों तथा किसानों के हितों से सम्बन्धित प्रश्नों को जोड़ें.

महासचिव की रिपोर्ट में कुछ राज्य कमेटियों तथा खासकर प. बंगाल राज्य कमेटी की सराहना की गयी, जिसने निकारागुआ की जनता के साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष के लिए एकजुटता की व्यवहारिक अभिव्यक्ति के रूप में, एकजुटता फंड के लिए भारी मात्रा में सामग्री तथा धन इकट्ठा किया है. ऐसे प्रयासों को जारी रखने के आह्वान के साथ ही, रंगभेदी प्रिटोरिया निजाम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की जनता के संघर्ष में सहयोग के लिए चन्दा इकट्ठा करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. रिपोर्ट में, समाजवाद की हिफाजत के लिए मजदूरों के रोजमर्रा के संघर्ष के अभिन्न हिस्से के तौर पर शांति के लिए संघर्ष तेज करने और मजदूरों तथा आम जनता के सामने अमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध की मुहिम को बेनकाब करने का आह्वान किया गया. कार्यकर्त्ताओं पर हत्यारे हमलों का सामना करते हुए संघर्ष जारी रखने के लिए, विभिन्न राज्य कमेटियों तथा यूनियनों को महासचिव की रिपोर्ट में बधाई दी गयी.

रिपोर्ट पर बहस

रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लेते हुए, विभिन्न राज्यों के वर्किंग कमेटी सदस्यों ने मई दिवस शताब्दी के पालन समेत उपर्युक्त कार्यक्रमों तथा अभियानों के सिलसिले में अपने अनुभव प्रस्तुत किये. प. बंगाल के मोहम्मद अमीन, नीरेन घोष तथा बीरेन राय ने रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने, पृथकतावादी गोरखालैंड आंदोलन के बारे में बताया और इस संदर्भ में भारत सरकार की भूमिका की भर्त्सना की. उन्होंने बताया कि किस प्रकार प. बंगाल वाम मोर्चा सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद नेपालीभाषी जनता की हालत सुधारने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की है. इस सिलसिले में उन्होंने, पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ मजदूर वर्ग तथा प. बंगाल की जनता के दृढ़ निश्चयी संघर्ष तथा खासकर चायबगान मजदूरों के प्रतिरोध को रेखांकित किया, जिन्होंने 11 सितम्बर को ही एक सफल हड़ताल का आयोजन किया है. उन्होंने बताया कि पृथकतावादी आंदोलन के खिलाफ मजदूर वर्ग तथा जनता का सक्रिय प्रतिरोध तेज हो रहा है और राज्य की वाम मोर्चा सरकार इस पृथकतावादी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर दृढ़ निश्चय प्रयास कर रही है. उन्होंने जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर 7 सितम्बर को हुए देहात बन्द तथा सफल हड़ताल, शांति के लिए विराट जन कार्रवाईयों, मई दिवस शताब्दी वर्ष के साल भर चले आयोजनों, उद्योगों में बढ़ती बीमारी तथा मिलबंदियों के प्रति—जिनसे अकेले प. बंगाल में 60 हजार से ज्यादा मजदूर प्रभावित हुए हैं—केन्द्र सरकार के उदासीनतापूर्ण रुख और कपड़ा, कागज तथा दूसरे उद्योगों की स्थिति की चर्चा की.

केरल के के एन रवीन्द्रनाथ तथा बी बी चेरियन ने रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए सरकार की नीतियों के चलते राज्य के परम्परागत उद्योगों में पैदा हो गये गम्भीर संकट को रेखांकित किया और काजू तथा ताड़ी मजदूरों, दस्तकारों तथा मछुआरों आदि असंगठित तबकों को संयुक्त संघर्षों के जरिये संगठित करने के प्रयासों के बारे में बताया. उन्होंने बेकारी-विरोधी अभियान के बारे में भी बताया, जिसके अंतर्गत बेरोजगारों की एक कन्वेन्शन का आयोजन किया गया था—जिसमें खेतमजदूरों समेत लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था—और अब काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने तथा रोजगार न मिलने तक बेकारों को बेकारी भत्ता देने की मांग को लेकर अक्टूबर में जत्थों का आयोजन किया जायेगा.

पंजाब के मंगतराम पासला ने खालिस्तानी उग्रवादियों के हत्यारे हमलों के बीच मजदूरों के संघर्षों को जारी रखने के जोखिम भरे अनुभव से वर्किंग कमेटी को परिचित कराया और बताया कि किस प्रकार सीटू ने फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ

समूचे मजदूर वर्ग को संगठित करने में प्रमुख एकताकारी शक्ति की भूमिका अदा की है.

इसी प्रकार, असम के अमल घोष दस्तीदार ने फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए, मजदूरों के एकजुट संघर्षों को आगे बढ़ाने के राज्य कमेटी के अनुभव से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार असम गण परिषद सरकार अपने चुनाव वादों को पूरा करने में विफल रही है जिसके कारण जनता में यहां तक कि असम गण परिषद समर्थकों में भी, असन्तोष बढ़ता जा रहा है. उन्होंने बताया कि गोरखालैंड आंदोलन का प्रभाव असम पर भी पड़ा है, जहां नेपालियों का एक हिस्सा पृथकतावादियों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है.

एन प्रसाद राव तथा बालाजी दास (आंध्र प्रदेश), ए के पद्मनाभन (तामिलनाडु), सूर्यनारायण राव (कर्नाटक), प्रभाकर सांझगिरि (महाराष्ट्र), शिवाजी पटनायक (उड़ीसा), योगेश्वर गोप (बिहार) रवि सिन्हा (उत्तर प्रदेश) तथा श्रद्धानंद सोलंकी (हरियाणा) ने रिपोर्ट पर बहस में हिस्सा लिया और उपयुक्त कार्रवाइयों के क्रम में अपने अनुभव प्रस्तुत किये.

फेडरेशनों की स्थिति

स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया के जीवन राय ने इस्पात उद्योग में फैल रहे संकट, श्रम शक्ति को धीरे-धीरे घटाये जाने, इंडिया आयरन एन्ड स्टील कम्पनी तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीरण करने की जरूरत के प्रति भारत सरकार के उदासीनतापूर्ण रुख और इस्पात मजदूरों के संघर्ष पर प्रकाश डाला.

आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के सुनील बसुराय ने खदानें बन्द किये जाने के कारण कोयला खदानों में उत्पन्न स्थिति का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि 22 कोयला खदानें बन्द होने के कगार पर हैं और भारत सरकार कोयले का आयात कर रही है. उन्होंने, कोयला मजदूरों के बढ़ते एकजुट संघर्षों पर प्रकाश डाला.

आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग बीमेंस की ओर से बोलते हुए विमल रणदिवे ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्य कमेटियों ने कामगार महिलाओं की समन्वय समितियों के गठन का काम शुरू कर दिया है. फिर भी, उनका, कहना था कि अब भी इस काम के सिलसिले में बहुत कुछ किया जाना बाकी रहता है. उन्होंने कहा कि महिला मजदूर ही स्वचालन तथा मशीनीकरण का सबसे पहले निशाना बनती हैं. उन्होंने चौथे आयोग की रिपोर्ट की आलोचना की, जिसमें दो बच्चों के बाद मातृत्व लाभ बन्द कर देने की सिफारिश की गयी है. उन्होंने विभिन्न संघर्षों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी की ओर भी ध्यान खींचा और राज्य कमेटियों का आह्वान किया कि महिलाओं की विशेष समस्याओं पर और ज्यादा ध्यान दें.

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के, के के राय गांगुली ने इस उद्योग में एकजुट संघर्ष और नौपरिवहन मंत्रालय तथा प्रबंधकों को पिछले समझौते लागू करने के लिए मजबूर करने के वास्ते अन्य फेडरेशनों को एकजुट करके संघर्ष चलाने में सीटू की एकताकारी भूमिका के बारे में बताया. इस प्रकार महा-सचिव की रिपोर्ट पर बहस' का समापन हुआ.

इसके बाद बी टी आर ने एटक अध्यक्ष चतुरानन मिश्र की चिट्ठी पढ़कर सुनायी, जिसमें उन्होंने, विभिन्न मसलों पर संयुक्त कार्रवाई के लिए, सीटू के साथ हर राज्य में संयुक्त कार्रवाई कमेटी गठित करने की पेशकश की है. बैठक ने सेक्रेटेरियट को अधिकृत किया कि वह चतुरानन मिश्र को जवाब दे.

बी टी आर ने अगले सीटू सम्मेलन, सम्मेलन की तारीखों तथा स्थान आदि का मसला विचार-विमर्श के लिए उठाया. उनकी राय थी कि सम्मेलन प. बंगाल तथा केरल के विधान सभा चुनावों के बाद अप्रैल या मई में किसी समय होना चाहिए. महाराष्ट्र इकाई से पूछा गया कि क्या वह सम्मेलन की मेजबान बन सकती है. प्रभाकर सांझगिरि ने राज्य कमेटी में विचार-विमर्श के बाद महीने भर के अंदर-अंदर जवाब भेजने का वचन दिया.

सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस के दौरान उठे सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बहस से इस बात की पुष्टि हुई है कि अपनी सही नीतियों तथा एकजुट संघर्षों के पथ पर दृढ़ रहने के चलते सीटू, भयंकर दमन के बावजूद आगे बढ़ रही है. उन्होंने, संगठन को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र कार्रवाइयों को तेज करने और इसके साथ ही अपनी एकताकारी भूमिका को जारी रखने का आह्वान किया. उन्होंने यह आह्वान भी किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आगामी कन्वेंशन को सफल बनाने के लिए व्यापकतम लामबंदी सुनिश्चित की जाय.

बी टी आर ने, सी पी आइ के नेता दर्शन सिंह कनाडियन की पंजाब में खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा हत्या किये जाने पर एक प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

बी टी आर का समापन भाषण

बहस का समाहार करते हुए बी टी आर ने कहा कि सीटू यूनियनों को भयंकर दमन का सामना करते हुए, मजदूरों को उनके जायज हक दिलाने के लिए कठिन लड़ाई चलानी पड़ रही है. यह बात उन राज्यों पर तो और भी लागू होती है, जहां आंदोलन कमजोर है और जहां की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि वहां किसी तरह के श्रम कानून है ही नहीं. मजदूरों के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए सीटू यूनियनों को भारी

कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं. फिर भी, उन्होंने याद दिलाया कि हम मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकती हैं, वी टी आर ने आगे कहा कि संगठन की इकाइयों से गलतियां हो सकती है, लेकिन गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, बरना किसी भी तरह का विकास या प्रगति कैसे संभव होगी? उन्होंने राज्य कमेटियों से आग्रह किया कि नियमित रूप से रिपोर्ट भेजें और एक अखिल भारतीय चेतना विकसित करें. उनका कहना था. कि संघर्ष चलाना, किंतु उसकी रिपोर्ट न भेजना, फैक्ट्री चेतना का ही संकेत करता है. किसी भी राज्य में होनेवाली छोटी से छोटी प्रगति भीं समूचे मजदूर वर्ग की प्रगति का अभिन्न हिस्सा है और अखिल भारतीय स्तर पर उस पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए. यानी, किसी खास राज्यों में मजदूर बर्ग के संघर्षो को दूसरों से छिपाकर नहीं रखा जाना चाहिए, बी टी आर ने बेरोजगारों, कामगार महिलाओं तथा असंगठित मजदूरों से सम्बन्धित आंदोलनों, को विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि इन तबकों की उपेक्षा करने का मतलब होगा, मजदूर वर्ग के एक बहुत वड़े हिस्से की उपेक्षा करना. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे संगठनों ने तों कामगार महिलाओं के लिए अलग से कमेटियां गठित की हुई है. उन्होंने, महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभों के सिलसिले में चौथे वेतन आयोग की प्रतिगामी फ़िफारिशों के प्रति केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों की उदासीनता की आलोचना की.

बी टी आर ने कहा कि यह जरूरी है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन, निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के हमले से राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत करने की लड़ाई को अपने हाथो में ले. यूनियनों के जनतांत्रिक ढंग से कामकाज करने के महत्व को रेखांकित करते हुए बी टी आर ने कहा कि सिर्फ संबिधान के अनुसार काम करने की जनतांत्रिक ढंग से काम करना नहीं कहा जा सकता. जरूरत इस बात की है कि सिर्फ संवैधानिक जरूरतें ही पूरी नहीं की जायें बल्कि सर्वहारा जनतंत्र को अमल में उतारा जाय.

बहस के दौरान एक सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न के संदर्भ में गोरखालैंड की मांग का विश्लेषण करते हुए बी टी आर ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साम्राज्यवाद दरवाजे पर खड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद-लेनिनबाद के अनुसार जातीयताओं के अधिकारों तथा आत्मनिर्णय की बात सही है. लेकिन, मार्क्सबाद-लेनिनवाद ही हमें यह सिखाता है कि हमें हर मसले को समाजवाद की दिशा में प्रगति की नजर से देखना चाहिए और अगर ये अधिकार समाजवाद के लक्ष्य के खिलाफ जाते हैं, अगर आत्मनिर्णय का मतलब देश से अलग होना है, तो मजदूरवर्ग को इन्हें सीधे-सीधे ठुकरा देना चाहिए, उन्होंने कहा कि भारत में क्रांति की सफलता की एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि देश एकजुट रहे और साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित पृथकता वादियों के खेल को शिकस्त दी जाय. नेपालियों के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को भारत-नेपाल संधि को रद्द कराने और देश का एक हिस्सा नेपाल के हवाले कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. वी टी आर ने पूछा कि क्या भारत का मजदूर वर्ग यह चाहेगा कि उसका एक हिस्सा साम्राज्यवादी तिकड़मों के हवाले कर दिया जाय?

उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने की साजिशें बहुत गहरी हैं. साम्राज्यबादी, भारतीय सेना के एक बाजू —सिखों —को तो पहले ही कमजोर कर चुके हैं. अब वे सेना के दूसरे बाजू —गोंरखाओं — को भी कमजोर करने पर तुले हुए हैं. इसलिए, यह जरूरी है कि पृथकतावादी साजिशों का प्रशासनिक ढंग से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी मुकाबला किया जाय. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भारत सरकार सिर्फ प्रसाशनिक उपायों का ही सहारा लेती है, जिससे समस्या हल नहीं हो सकती है.

सौभाग्य से प. बंगाल में मजदूर वर्ग के लिए अनुकूल स्थिति यह है कि प्रसाशनिक तथा राजनीतिक, दोनों स्तरों पर संघर्ष चलाना संभव हो रहा है, बी टी आर ने कहा कि गोरखालैंड आंदोलन को सिर्फ सीटू या सी पी आई (एम) पर ही हमले के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यह हमला देश के समूचे मजदूर वर्ग पर है और यह देश को अस्थिर करने की साम्राज्यवादी साजिशों का अभिन्न अंग है इसलिए, सीटू का यह दायित्व वनता है कि पूरी ताकत लगाकर पृथकताबादी चुनौती का मुकाबला करने के लिए, देश भर के मजदूर 'वर्ग को लामबंद करे.

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन कांग्रेस की रिपोर्ट

सीटू कोषाध्यक्ष ई बालानंदन ने 16 से 22 सितम्बर तक बर्लिन में संपन्न हुई वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस पर रिपोर्ट पेश की. विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मुख्य दस्तावेज युद्ध के खतरे के खिलाफ तथा शांति के लिए संघर्ष, बहुराष्ट्रीय निगमों, दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद निजाम, ट्रेड यूनियन अधिकारों, रोजगार अल्पकालिक रोजगार आदि के प्रश्नों पर केन्द्रित था. युद्ध के खिलाफ तथा शांति के लिए संघर्ष के क्रम में कांग्रेस ने रोनाल्ड रीगन, मिखाईल गोर्वाचोब तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के नाम एक अपील स्वीकार की. कांग्रेस में सीटू कोषाध्यक्ष ई बालानंदन के भाषण का जबर्दस्त स्वागत किया गया, जिसमें बहुत ही सही तथा सुसंगत ढंग से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को रखा गया था. इस कांग्रेस ने, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद के झंडे को बुलंद रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग को एकजुट करने के अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के निश्चय को दोहराया.

सीटू वर्किंग कमेटी अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये, जिसमें शांति के लिए संघर्ष, गोरखालैंड आंदोलन, पंजाब, फूटपरस्त ताकतों, सार्वजनिक क्षेत्र, चौथे वेतन आयोग, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका, निकारागुआ, नई आर्थिक नीति के खिलाफ संघर्ष, जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण, बेकारी, मई दिवस

(शेष पृष्ठ 24 पर)

सीटू वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

शहीदों पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर, 1986 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक उन साथियों की याद में अपने लाल झंडे को झुकाती है जिन्होंने मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के हितों के प्रति अपने समर्पण के कारण मालिकान के गुंडों एवं पुलिस की गोलियों के शिकार होकर शहीद हुए. यह बैठक उनके अधूरे कामों को पूरा करने की शपथ लेती है.

कामरेड ले दुआन

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर 1986 तक हुई सीटू कार्यकारिणी की बैठक वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कामरेड ले दुआन के निधन पर गहरे शोक का इजहार करती है. कामरेड ले दुआन का निधन 10 जुलाई को हेनोय में हुआ.

एक मजदूर परिवार में जन्मे कामरेड ले दुआन मार्क्सवाद-लेनिनवाद में विश्वास रखने वाले इस युग के महानतम नेताओं में से थे और मजदूर वर्ग तथा वियतनाम क्रांति, जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, के एक महान नेता थे, मार्क्सवाद-लेनिनवाद में अटल विश्वास के कारण ही वे फ्रांसीसी तथा जापानी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम के मजदूर वर्ग तथा वियतनामी जनता के जुझारू संघर्ष में काम करते रहे और फिर बाद में दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी युद्ध मशीन—अमरीका को शिकस्त देते हुए दक्षिण हिस्से को मुक्त कराने और देश को फिर से एक करने का काम को भी पूरा किया. उन्हींके नेतृत्व में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्पूचिया में, पोल पोट निजाम के साजिशों के खिलाफ, क्रांति की रक्षा करने में सहायता देने की अपनी सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावादी जिम्मेदारी पूरा किया.

युद्ध से ध्वस्त एक देश के नेता के रूप में कामरेड ले दुआन विश्वशांति को बहुत महत्व देते थे और सच्ची शांति के लिये सोवियत संघ तथा समाजवादी समूदाय के सभी प्रस्तावों का हार्दिक स्वागत करते रहे थे. इसके साथ ही, वह साम्राजी धमकियों तथा ब्लैकमेल के सामने कभी झुके नहीं और अपने क्रांतिकारी जीवन के तमाम सालों में बार-बार इस बुनियादी सच्चाई को रेखांकित किया कि जबतक साम्राज्यवाद का खात्मा नहीं हो जाता है, सच्ची तथा स्थाई शांति कायम नहीं हो सकती है.

यह कार्यकारिणी की बैठक इस महान दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने लाल झण्डे को झुकाती है तथा वियतनाम फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स, वियतनाम के मजदूर वर्ग तथा जनता एवं उनके शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

श्रद्धांजलि पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक उन तमाम कामरेडों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने समाजवाद की स्थापना में अपने क्रांतिकारी संघर्षों के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया. यह बैठक उनके शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

शांति के लिए संघर्ष पर

सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक, जो नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर 1986 तक हुई राज्य कमेटियों का, खासकर, प. बंगाल, केरल और त्रिपुरा तथा सम्बद्ध यूनियनों का हार्दिक अभिनंदन करती है जिन्होंने व्यापक रूप से हिरोशिमा और नागासाकी दिबस तथा 1 सितम्बर शांति दिवस को मनाया. विश्व शांति और युद्ध के बढ़ते खतरे के सवाल पर ट्रेड यूनियनों के बीच विकसित हो रही एकता पर यह बैठक प्रसन्नता व्यक्त करती है और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा अक्टूबर में निरस्त्रीकरण दिवस मनाए जाने की फैसले का स्वागत करती है.

बैठक अपने राज्य कमेटियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती है कि शांति के लिए संघर्ष का निर्माण के उनके प्रयासों के बाबजूद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की मांग की तुलना में इस महत्वपूर्ण मुद्देपर उनका सहयोग अभी भी कम है. सोवियत संघ द्वारा पेश किए गए एक के बाद एक शांति प्रस्तावों को ठुकराकर अमरीकी साम्राज्यवाद अपने अंतरिक्ष युद्ध के कार्यक्रम और नए नए नाभिकीय हथियारों की जखीरा खड़ा करने पर तुली हुई है. नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की छः राष्ट्रों की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की तथा दुनियां भर के शांतिकामी लोगों की अपील की उपेक्षा करने तथा 1986 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के रूप में मनाने की राष्ट्र संघ के आह्वान के बावजूद नाभिकीय परीक्षण जारी रखने की मुहिम के लिए यह बैठक रीगन प्रशासन की तीव्र भर्त्सना करती है. यह बैठक, सोवियत संघ की सराहना करती है जिसने इस आह्वान पर अमल किया और एक तरफा रूप से 1 जनवरी 1987 तक तमाम नाभिकीय परिक्षणों पर प्रतिबंध की घोषणा की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति बर्ष के आह्वान के प्रति जबर्दस्त योग दान है.

ऐसी परिस्थिति में, राज्य कमेटियों द्वारा शांति संघर्षो को आगे बढ़ाने के लिएजो भी कुछ किया गया वह अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी पूरा करने के लिए नाकाफी है. अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों के खिलाफ संघर्ष में जनता के व्यापक हिस्से को लामबंद करना जरूरी है. इसलिए, यह बैठक, अपने राज्य-

कमेटियों एवं सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वह व्यापक शांति संघर्ष के निर्माण के अपने प्रयासों को दुगना करते हुए रीगन प्रसाशन से अंतरिक्ष युद्ध कार्यक्रम को रोकने, नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने और होने वाले शिखर-वार्ता को सफलीभूत करने के लिए माहौल तैयार करने की मांग करें.

गुट निरपेक्ष सम्मेलन पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर 1986 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक हरारे में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के फैसले की सराहना करती है. सम्मेलन द्वारा स्वीकृत एकजुट फैसलों के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद, जियनवाद के खिलाफ तथा शांति और निरस्त्रीकरण के पक्षधर एक जबर्दस्त ताकत के रूप में उभरा है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक पाबन्दियां लागू करने तथा नस्लपरस्त निजाम की जबाबी पाबन्दियों का सामना करने में फ्रण्ट लाईन देशों को मदद करने और नामिबिया की मुक्ति के लिए गुटनिर्पेक्ष आंदोलन ने जो दृढ़तापूर्ण रुख अपनाया है उसके लिए यह बैठक आंदोलन का अभिनन्दन करती है. बोथा निजाम के प्रति समर्थन, लीबिया पर हमले और निकांरागुआ के सिलसिले में साम्राज्यवादी अमरीका और ब्रिटेन की सीधे-सीधे भर्त्सना और उनके खिलाफ गुटनिर्पेक्ष आंदोलन की दृढ़-निश्चयी रुख, से युद्ध के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं दक्षिण अफ्रीकी जनता के मुक्ति आंदोलन को बल मिलेगा.

उत्तर-दक्षिण आर्थिक सम्बन्धों में नाबराबरी खत्म करने के लिये उनका दृढ़ निश्चय, ऋण अदायगी और पश्चिमी देशों के संरक्षणवादी नीति के खिलाफ उनके कदम तथा एक नयी बिश्व आर्थिक प्रणाली के लिए संघर्ष को शक्तिशाली बनाने का उनके संकल्प के लिए यह बैठक गुट-निर्पेक्ष आंदोलन का अभिनन्दन करता है.

सीटू कार्यकारिणी, हरारे में भारत सरकार की आम्राज्य-वाद बिरोधी तथा नस्लवाद बिरोधी भूमिका की सराहना करती है और आशा करती है कि वह अपने इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती रहेगी जिससे भारतीय जनता की साम्राज्यबाद विरोधी संघर्ष को मदद मिलेगा.

यह बैठक, अपने राज्य कमेटियों तथा सम्वद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि हरारे शिखर सम्मेलन के फैसलों के प्रति हर तबके के मजदूरों को लामबन्द करें ताकि गुट निर्पेक्ष आंदोलन को और शक्तिशाली बनाया जाय और उसे विघटित करने की हर साम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम किया जाय.

दक्षिण अफ्रीका पर

24 से 26 सितम्बर 1986 तक नई दिल्ली में सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक नस्लबादपरस्त बोथा हुकूमत की तीव्र भर्त्सना करती है जो अपनी जनता पर बर्बर दमन और अत्याचार चला रखा है. दक्षिण अफ्रीका के अल्पमत श्वेत निजाम को लगातारूप से राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक मदद पहुंचाने के लिए यह बैठक अमरीका और ब्रिटिश साम्राजियें एवं अन्य पश्चिमि देशों का भी तीव्र भर्त्सना करती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अनुल्लंघनीय आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताबों पर अमरींका तथा ब्रिटेन की सरकारों द्वारा बारबार वीटो प्रयोग करने की भी यह बैठक तीव्र निंदा करती है. सस्ते श्रम का बेतहाशा शोषण कर अपने बहुराष्ट्रीय निगमों के मुनाफा बढ़ाने में दक्षिण अफ्रिका में जो लूट मचा हुआ है उसका अधिकतम हिस्सा इन्हीं दो देशों के पल्ले जाता है. अपने इजारेदारों के हितों की रक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीकी जनता को गुलाम बनाए रखना साम्राज्यवादी लक्ष्यों को हासिल करने की अमरीकी नीति का ही एक हिस्सा है. उनके इस खुले समर्थन से ही नस्लबादपरस्त हुकूमत को अपनी जनता पर बर्बर अत्याचार चलाने तथा फ्रण्ट लाईन देश जिम्बावे, जाम्बिया, बोत्सवाना एवं एंगोला पर भी हमला बोलने की हिम्मत दिला रहा है.

यह बैठक, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ए एन सी) की अगुवाई में चल रही दक्षिण अफ्रीकी जनता की मुक्ति आंदोलन के साथ सी आई टी यू की एकजुटता को दुहराती है और घृणित नस्लपरस्त निजाम के खिलाफ एक दृढ़ निश्चयी रुख अपनाने के लिए गुट निर्पेक्ष देशों का अभिनन्दन करती है. यह बैठक नस्लवादी हुकूमत से, तत्काल नेलसन मण्डेला एवं अन्य राज-नीतिक बन्दियों को रिहा करने की मांग करती है. बैठक, अमरीका, ब्रिटेन एवं अन्य पश्चिमी देशों से बोथा निजाम के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध थोपने की मांग करती है. बैठक इस बात पर सन्तोष प्रकट करता है कि इस सवाल पर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एकजुट हैं और पिछले 16 जून को संयुक्तरूप से नस्लवाद विरोधी दिवस मनाया है. दक्षिण अफ्रीकी जनता के लिये एक फण्ड-एकजुटता फण्ड के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा लिए गये फैसले का भी यह बैठक समर्थन करती है और अपने राज्य कमेटियों एवं सम्बद्ध यूनियनों से इस कोष में उदारता से अंशदान देने के लिये आह्वान करती है.

निकारागुवा पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर, 1986 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी कीयह बैठक अपने उन राज्य कमेटियों एवं सम्वद्ध यूनियनों को बधाई देती है जिसने निकारागुवा के क्रांति-कारी सैन्डिनिस्टा सरकार की अपील के तहत निकारागुवा एक जुटता फंड में अंशदान दिए है. यह बैठक, खासकर प. बंगाल राज्य कमेटी को बधाई देती है जिसने विभिन्न संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों को लेकर एकजुटता कमेटी का गठन किया और कुछ ही समय के अन्दर 4.6 लाख रू की बिशाल रकम एवं अन्य सामान इकठ्ठा कर लिया है. प. बंगाल एवं अन्य कमेटियों

एवं यूनियनों ब मजदूरों द्वारा इकठ्ठा कीं गई यह रकम सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा ऊंचा उठाने की उनके अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाने का ही एक हिस्सा है जिसके जरिए उन्होंने निकारागुवा की जनता और सैन्डिनिस्टा सरकार की मदद की है जो अपने देश की संप्रभुता और आजादी को नष्ट करने की अमरीकी साम्राज्यवादी साजिशो के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. अमरीकी साम्राज्यवाद, दुनिया पर प्रभुत्व की अपनी मुहिम में क्रांतीकारी सरकार को गिराने की हर तरह के जघन्य साजिश में लगी हुई है. प्रति क्रांतिकारी कंट्राओं को प्रत्यक्ष रूप से मदद देने के अलावा उन लोगों ने समूदी अवरोध संगठित कर निकारागुवा सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दिया है और इस तरह पूर्व समोजा निजाम द्वारा बर्बाद किए गए देश की अर्थनीति के पुनर निर्माण में लगे सरकार के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं अब वे निकारागुवा के खिलाफ सीधी सैनिक कार्रवाई का भी धमकी दे रहे हैं. यह बैठक निकारागुवा की जनता के संघर्ष के साथ सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है और अपने राज्य कमेटियों एवं यूनियनों का आह्वान करती है कि वे निकारागुवा की क्रांतिकारी सरकार को मदद भेजना जारी रखें.

फूटपरस्त ताकतों पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर 1986 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक 9 अगस्त 1986 को देश भर में व्यापकरूप से राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाने के लिए देश के मजदूर वर्ग को बधाई देती है. यह बैठक विशेष रूप से सी आई टी यू राज्य कमेटियों एवं यूनियनों को, रैलियां, सेमिनार आदि के आयोजन पर पहल के लिए तथा कई जगहों पर एक हफ्ते तक इस कार्यक्रम को चलाने के लिए बधाई देती है. बहरहाल यह बैठक चिंता के साथ इस बात को नोट करती है कि कई स्थानों पर नए शक्तियों के उभार के साथ फूटपरस्त ताकतों की हरकतें तेज होती नजर आ रही है. जबकि पंजाब की स्थिति अब भी खतरनाक बनी हुई है, जी एन एल एफ देश को विघटित करने की एक और नई शक्ति के रूप में सामने आ रही है गुजरात में फिरसे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठी है. असम, कर्नाटक आदि राज्यों में अल्प संख्यकों पर बहुसंख्यकों की भाषा थोंपे जाने की प्रयास के कारण भाषायी आधार पर जनता का ध्रुवीकरण हुआ है और आंदोलन भड़क उठा है. मिजोराम समझौता के बाद भी लाल डेंगा ने बृहत्तर मिजोरम की अपनी मांग को नहीं छोड़ा है. उन्हें महत्व दिये जाने के फलस्वरूप उत्तरी पूर्व क्षेत्र के अन्य भागों में बिघटन कारी ताकतों को बढ़ावा मिला है. त्रिपुरा में, टी एन वी उग्रवादियों ने आम जनता पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं. जम्मू-कश्मीर में भी स्थिति सामान्य नहीं है.

साम्राज्यवादी एजेंसियों के पैसे और मदद प्राप्त ये फूटपरस्त ताकतें देश को टुकड़ें-टुकड़े करने पर तुली हुई है.

इस परिस्थिति में, जब राष्ट्रीय अखण्डता की समस्या बद से बदतर होती जा रही है, केन्द्र की कांग्रेस(आई) सरकार, इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए जनता का आह्वान करने के बजाय उनसे समझौता करती जा रही है और अपने संकीर्ण चुनावी लाभों के लिए राष्ट्रीय हित को ही दांव पर लगा रही है. यह बैठक भारत सरकार से मांग करती है कि वह फूटपरस्त ताकतों को खुश करने और उससे समझौता करने की अपनी नीति को त्याग दें.

इन परिस्थितियों में, ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ इन फूटपरस्त ताकतों को रोकना चाहिए और साम्राज्यवादियों के इस खेल को शिकस्त देना चाहिए. इसलिए, कार्यकारिणी की यह बैठक अपने राज्य कमेटियों एवं यूनियनों का आह्वान करती है कि वे मजदूरों के व्यापक हिस्से को तथा लोगों को और धर्मनिर्पेक्ष व जनवादी ताकतों को लामबन्द करते हुए देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए इन फूटपरस्त ताकतो के खिलाफ संघर्ष को तीव्र करें.

गोर्खालैंड आंदोलन पर

नई दिल्ली में 24 से 26 सितम्बर 1984 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक प. बंगाल में गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट द्वारा अलग गोर्खालैंड के लिए चलाइ जा रही आंदोलन की तीव्र भर्त्सना करती हैं. यह साम्राज्यवादी एजेंसियों की पैसे से चलाई जा रही पृथकतावादी आंदोलन है जो देश को टुकड़े-टुकड़े करने की अन्य फूटपरस्त हरकतों के साथ जुड़ा हुआ है. यह बैठक, प्रधानमन्त्री एवं अन्य कांग्रेस(आई) नेताओं के उन बयानों की भी भर्त्सना करती है जिसमें यह कहा गया है कि गोर्खालैंड आंदोलन राष्ट्रविरोधी नहीं हैं, बावजूद इसके कि आंदोलन के नेताओं ने खुले तौर पर बाहरी देशों से जैसा नेपाल तथा पाकिस्तान एवं अमरीका और ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी देशों से मदद मांगा है. यह बहुत खेद की बात है कि प्रधानमन्त्री जो भारत के कर्णधार हैं, ने कभी भी कामरेड आनन्द पाठक जो कि एक सांसद है तथा सीटू एवं सी पी आई(एम) के नेता हैं, का घर जलाए जाने तथा आगजनी, हत्या एवं हिंसक घटनाओं की निंदा तक नहीं की.

यह बैठक, देश के मजदूरवर्ग का तथा जनता के हर हिस्से का ध्यान इस ओर खींचती है कि वाम मोर्चा सरकार ने ही नेपाली भाषा को राज्य की सरकारी भाषाओं में से एक का दर्जा दिया, स्कूलों में इस भाषा को पढ़ाए जाने कीं व्यवस्था की और केन्द्र सरकार से यह मांग की कि नेपाली भाषा को संविधान में शामिल किया जाय और प. बंगाल के नेपाली भाषी इलाके को क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जाय. पर भारत सरकार ने इन मांगों को मंजूरी देने से इंकार कर दिया और अब आंदोलन को बढ़ावा दे रही है.

यह बैठक, उग्रवादियों को अलग-थलग करने और दृढ़ प्रशासनिक कदमों के अलावा अपने राजनीतिक व सिद्धांतवादी अभियान के जरिए देश की अखण्डता की रक्षा के लिए उनके संकल्पपूर्ण प्रयासों के लिए वाम मोर्चा सरकार का अभिनन्दन

करती है. यह बैठक प. बंगाल के मजदूरवर्ग एवं तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों तथा धर्मनिर्पेक्ष व जनवादी ताकतों को भी, पृथकतावादियों के हरकतों को रोकने के लिये सही समय पर हस्तक्षेप करने और संघर्ष चलाने के लिए बधाई देती है. यह बैठक, खासकर बंगाल के चाय बागान मजदूरों को उनके 11 सितम्बर की शानदार एकजुट हड़ताल के लिए बधाई देती है जो जी एन एल एफ गुंडों पर एक करारा प्रहार के समान था. बहरहाल, इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि विघटनकारी ताकतें अपनी हरकतपूर्ण गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, यह बैठक अपनी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों का आह्वान करती है कि गोर्खालैण्ड आंदोलन को बेनकाब करने और शिकस्त देने के लिए वे अपने संघर्ष को तेज करें.

सीटू का बर्दवान जिला सम्मेलन

6 और 7 अक्टूबर को रूपनारायण पुर के शहीद पारितोष सिल तथा मिहिर डे मंच पर सीटू का दूसरा बर्दवान जिला सम्मेलन संपन्न हुआ. सम्मेलन के लिए, जिले के 1 लाख 10 हजार सीटू सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे 438 प्रतिनिधियों तथा 31 प्रेक्षकों के अलावा 13 बिरादराना प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया.

6 सितम्बर को दोपहर बारह बजे सीटू अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने संगठन का झंडा फहराया तथा शहीद स्तम्भ पर फूलमालाएं चढ़ाई और इस तरह सम्मेलन की कार्रवाई शुरू हुई. सम्मेलन के अपने उदघाटन भाषण में सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने सार्वजनिक क्षेत्र के नवीकरण तथा खात्मे की राजीव सरकार की नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था के ही कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है, उन्होंने कहा कि अगर यह रूझान जारी रहने दिया जाता है तो हमारे देश कीं गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के लिए ही खतरा बढ़ जाएगा और देश की विदेश नीति साम्राज्यवादी युद्धोन्मादियों के पक्ष में झुक जाएगी जोकि हमारे देश के हितों के लिए खतरनाक होगा. उन्होंने याद दिलाया कि अमरीकी साम्राज्यवादियों ने शत्रुतापूर्ण हुकूमतों तथा सैनिक अड्डों से, हमारे देश को घेर लिया है.

बी टी आर ने आगे कहा कि मजदूर वर्ग को अपने एकजुट आंदोलन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करनी होगी. पृथकतावादी आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत ही देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा कर सकती है इसके साथ ही उन्होंने सांप्रदायिक, पृथकतावादी तथा अन्य फ़ूटपरस्त ताकतों की चालों के बारे में निरंतर सजग रहने का आह्वान किया. संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने मौजूद दूसरे कामों का जिक्र करते हुए बी टी आर ने कहा कि बेकारी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ बेरोजगारों को ही नहीं बल्कि रोजगार में लगे लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए. इसी प्रकार उन्होंने, बड़े तथा छोटे उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों में भी, असंगठित मजदूर वर्ग को संगठित करने की जरूरत पर जोर दिया. सम्मेलन में, कामगार महिलाओं का कोई विशेष प्रतिनिधित्व न होने के तथ्य की ओर ध्यान खींचते हुए बी टी आर ने ट्रेड यूनियनों के झंडे तले महिला मजदूरों को संगठित करने की जरूरत पर जोर दिया, उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि अपनी चेतना का विकास करें और एक ऐसी ताकत का रूप लें जो, पूंजीवादी-भूस्वामी शासक वर्गो के चौतरफा हमले का मुकाबला करने में समर्थ हो बी टी आर ने इस बात पर भी जोर दिया कि मजदूर वर्ग अपनी आर्थिक मांगों में ही न उलझा रहे बल्कि उसे दुनियां भर में, देश भर में, जनतांत्रिक तथा प्रगतिशील ताकतों के संघर्ष से जुड़ना चाहिए. उन्होंने युद्ध के खिलाफ तथा शांति के लिए, मजदूर वर्ग को संगठित करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

बी टी आर के उद्घाटन भाषण के बाद, जिला सीटू महासचिव बामपद मुखर्जी ने सचिवमंडल की ओर से रिपोर्ट पेश की और हिसाब-किताब का ब्यौरा दिया. रिपोर्ट पर हुई बहस में 33 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, बहस के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गए प्रश्नों का जबाब देने के बाद रिपोर्ट तथा हिसाब-किताब को सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया. अंत में सम्मेलन ने 51 सदस्यीय वर्किंग कमेटी तथा पदाधिकारिय का चुनाव किया और बिजय पाल अध्यक्ष और बामपद मुखर्जी महासचिव चुने गये.

सम्मेलन ने युद्धके खिलाफ तथा शांति के पक्ष में, केंद्र सरकार के जनविरोधी बजट तथा मूल्यवृद्धि के खिलाफ, बंद तथा बीमार उद्यमों को खोलने, मजदूर-किसान एकता, बाममोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति को हिमायत में, राजीव सरकार की नई आर्थिक नीति के खिलाफ, जूट तथा कपड़ा उद्योगों के सिलसिले में, काकगार महिलाओं के सम्बन्ध में आदि नौ प्रस्ताव स्वीकार किये.

संपादक मंडल

पी. राममूर्ति (चेयरमेन)

मनोरंज राय, नीरेन घोष,

एम. एम. लारेंस, पी. के. गांगुली

एम. के. पंधे (सम्पादक)

(पृष्ठ 19 का शेष)

शताब्दी आयोजन, बोकारो इस्पात कारखाने की प्रस्तावित हड़ताल आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव मुख्य है.

प. बंगाल के आगामी चुनावों पर

कॉमरेड बी.टी.आर. ने 'प. बंगाल के चुनावों पर' प्रस्ताव पेश किया जिसमें प. बंगाल के मजदूरवर्ग से बाम मोर्चा उम्मीदवारों को फिर से चुनने और इस तरह देश में जनवाद की अग्रिम चौकी की रक्षा करने के लिए आह्वान किया. गोर्खालैंड आंदोलन तथा कांग्रेस(आई) द्वारा पैदा किए गये अन्य समस्याओं को देखते हुये मजदूरवर्ग को चुनाव में बाम मोर्चे के उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करना होगा.

प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कॉ. नृसिंह चक्रवर्ती ने प. बंगाल के अलावा अन्य राज्य कमेटियों का आह्वान किया कि वे इसे एक राजनीतिक जिम्मेदारी समझे और चुनावी लड़ाई में सहयोग दें. यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ.

इसके बाद बी टी आर ने मनोरंजन राय का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें गोरखालैंड आंदोलन के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने के लिए चंदे की अपील की गई थी. सीटू राज्य कमेटियों तथा फेडरेशनों ने तत्काल इस अपील पर गौर किया और चंदा देने का वादा किया. बैठक में ही 32,000 रू. के चंदे के वादे किये गये और, भी चंदा करने का वचन दिया गया. सीटू की केरल तथा महाराष्ट्र राज्य कमेटियों तथा प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन ने पांच-पांच हजार रू; असम राज्य कमेटी तथा ई ई एफ आई ने दो-दो हजार रू; बिहार राज्य कमेटी ने डेढ़ हजार रू.; आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उड़ीसा राज्य कमेटियों तथा स्टील वर्कर्स फेडरेशन, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, कोल वर्कर्स फेडरेशन, रोडट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, ताड़ी वर्कर्स फेटरेशन (केरल) तथा केरल स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज फेंडरेशन ने एक-एक हजार रू. और कर्नाटक, उ. प्र., पंजाब तथा हरियाणा राज्य कमेटियों ने पांच-पाँच सौ रू. देने का वादा किया हैं.

अंत में पी के गांगुली तथा एम के पंधे ने क्रमशः चीनी तथा सीमेंट उद्योगों पर रिपोर्टें पेश कीं, जिन पर विचार किया गया. इन उद्योगों में एकजुट संघर्ष चलाने के लिए प्रयास करने का फैसला लिया गया है.

इसके बाद पी सत्यनारायण ने क्रेडेशियल कमेटी की रिपोर्ट पेश की.

अंत में बी टी आर ने बैठक के लिए शानदार व्यवस्था करने के लिए दिल्ली राज्य कमेटी को बधाई देने के साथ बैठक का समापन किया.

चीन की राष्ट्रीय दिवस के मौके पर ए सी एफ टी यू को सीटू की बधाई

1 अक्तूबर को चीनी लोक जनवादी गणराज्य की स्थापना की सैंतीसवीं साल गिरह पर सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने ऑल चायना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस् के चेयरमैन को बधाई संदेश भेजा है. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीनी क्रांति की जीत 1 अक्तूबर 1949 को हुई थी. रूस के महान अक्टूबर क्रांति तथा जर्मन फासीवाद पर सोवियत लाल सेनाओं की जीत के बाद बहुत सारे देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की तथा समाजवाद की स्थापना के क्रम में चीनी क्रांति ही सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना थी.

'लंबी छलांग' एवं तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति की गलत नीतियों के कारण लगे गम्भीर धक्के से उबरने के सफल प्रयासों के बाद अब समाजवादी चीन, समाजवादी निर्माण तथा सामाजिक प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. ए सी एफ टीयू, (चीन) तथा भारत स्थित चीनी दूतावास को 30 सितम्बर को भेजे गए दो अलग अलग तार में बी. टी. रणदिवे ने हार्दिक अभिनंदन का इजहार किया और चीन को एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने की उनके प्रयासों की सफ़लता की कामना की.

सीटू प्रकाशन

रेलवे ट्रेड यूनियन का इतिहास
(एक अध्ययन)
लेखक नृसिंह चक्रवर्ती
अनुबादक शंकर दयाल तिवारी
कामरेड बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू
द्वारा लिखित भूमिका के साथ
पांच प्रतियों या उससे अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट

सम्पर्क करें:

1 सी आई टी यू
6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

2 नेशनल बुक सेन्टर
14, अशोक रोड
नई दिल्ली-110001.